

प्रेषक,
मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 01 सितम्बर, 2009

विशय:- डा0 राकेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को ग्राम किरसाली, तहसील एवं जिला देहरादून में 500 वर्गमीटर भूमि निजी आवास हेतु क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-74/12ए-693(2008-11)/ डी0एल0आर0सी0 दिनांक-26.08.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय डा0 राकेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन को निजी आवास हेतु कुल 500 वर्गमीटर भूमि ग्राम किरसाली तहसील एवं जिला देहरादून में क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता संख्या-49, खसरा संख्या-341 के अनुसार क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (निजी आवास) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो। इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 8- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 9- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 10- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 11- आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय करने से पूर्व अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली, 1968 के नियम-16(3) के अनुसार अपने नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी से अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी भी आवश्यक होगी।
- 12- प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल निजी आवास हेतु ही किया जायेगा एवं उसका किसी भी प्रकार से व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
- 13- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

प्र0प0सं0-2003/समदिनांकित 2009

- 2- सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- डा० श्री राकेश कुमार, सचिव शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- ✓ निदेशक एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
24
(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।